

यूटर्न टाइम्स

THE GOOD, BAD AND UGLY OF INDIA

FOLLOW US ON    @UTURNTIMENEWS

गुस्ताखी माफ

कुत्ता आवारा नहीं, सरकारी था यार।
सरकारी गोहू तनी, था वह रहा खिलार।
था वह रहा खिलार, तनी गोहू सरकारी।
उसको था अहसास, बेरियां सभी हजारी।
कह साहिल कविराय, प्रशासन रहता चुता।
राखी उनकी करे, यही सरकारी कुत्ता।

प्रस्तुति : डॉ. राजेन्द्र साहिल

Visit at : www.uturntime.com

संक्षिप्त खबरें

एयर इंडिया मादक द्रव्यों, वर्जित दवाओं के सेवन के लिए हर पायलट की करेगी जांच

नई दिल्ली, यूटर्न/ 13 अगस्त। टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने अपने हर पायलट की मादक द्रव्यों और वर्जित दवाओं के सेवन के लिए जांच करने का फैसला किया है। कंपनी ने उड़ान के बाद इस जांच को सभी पायलटों के लिए गुरुवार से अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला गत चार अगस्त को फुकेट-दिल्ली उड़ान के दौरान विमान के हवा में अचानक 300 फुट नीचे गोता लगाने की घटना के बाद किया गया है। नशीले पदार्थ के सेवन के लिए किये गये स्क्रीनिंग टेस्ट में उड़ान का मुख्य पायलट पॉजिटिव पाया गया था। उसका सैपल प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा गया है। उड़ान संख्या एआई 2379 के साथ हुई इस गंभीर घटना में 20 यात्री और चालक दल के चार सदस्य घायल हो गये थे। उड़ान में तीन शिशुओं समेत 137 यात्री और दो पायलट समेत चालक दल के आठ सदस्य थे। एयर इंडिया में उड़ान परिचालन के प्रमुख महेश उप्पल ने एयरलाइंस के पायलटों को आज एक पत्र जारी कर बताया, '...हमने ग्रुप के सभी पायलटों की उन सभी पदार्थों या दवाओं के लिए पूर्ण स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया है, जिनकी नियमों के तहत अनुमति नहीं है।

कर्नाटक विधानसभा परिसर में चल रही कैटीन की थाली में मिले कॉकरोच

बेंगलुरु, यूटर्न/ 13 अगस्त। कर्नाटक विधानसभा के अंदर चल रही कैटीन, जहां मंत्रियों और अधिकारियों के दफ्तर हैं, स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में साफ-सफाई से जुड़ी कमियां पाए जाने के बाद जांच के दायरे में आ गई है। विभाग ने विधान सभा परिसर में मौजूद विकास सौधा की कैटीनों में भी छापेमारी की। जांच में खाने की प्लेटों पर कॉकरोच नजर आए, जिससे कैटीन में साफ-सफाई के मानकों को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस परिसर में कई होटल हैं जहां विधायक ठहरते हैं, जो बेंगलुरु के बाहर से आते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग को लेजिस्लेटर्स हाउस में जांचे गए एक प्रतिष्ठान में घंटिया गुणवत्ता वाला खाना और गंदगी मिली थी। जांच से पता चला है कि विभाग ने सरकारी इमारतों में चल रहे खाने-पीने के ठिकानों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। इनमें मंत्रियों, अधिकारियों और विधायकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जगहें भी शामिल हैं।

भरत तिवारी के परिवार को मुआवजा और मिलेगी सरकारी नौकरी : सद्माट चौधरी

पटना, यूटर्न/ 13 अगस्त। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य सरकार यह सहायता मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर देगी। हालांकि, परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि दी जाएगी, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि भरत तिवारी की 17 जून को भोजपुर में पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई थी। घटना की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठने और परिवार की ओर से पुलिस के दावे पर सवाल उठाए जाने के बाद बिहार सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। परिवार ने मुठभेड़ को कथित तौर पर फर्जी बताया था, जबकि पुलिस अपने आधिकारिक दावे पर कायम है।

हंगामे के बीच संसद का मानसून सत्र समाप्त

लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, आखिरी दिन भी नहीं थमा गतिरोध

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 13 अगस्त।

भारी हंगामे और गतिरोध के बीच गुरुवार को भारी हंगामे और राजनीतिक गतिरोध के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही मानसून सत्र का औपचारिक समापन हो गया। सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही सुबह ही स्थगित करनी पड़ी। वहीं, राज्यसभा में 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' पारित होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा हल्लानी से जुड़े मुद्दे को उठाए जाने के बाद सदन की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई।

गुरुवार को मानसून सत्र का अंतिम दिन था। लोकसभा में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। भारी शोर-शराबे के बीच लोकसभा की कार्यवाही लगभग 11:05 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आमतौर पर सदन की कार्यवाही शाम तक चलती है, लेकिन आज सुबह ही स्थगन हो गया। इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित



शाह भी मौजूद रहे।

राज्यसभा में भी गतिरोध

राज्यसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' पारित हो गया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्लानी में उनके कार्यक्रम के बाद कथित शुद्धिकरण अनुष्ठान का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर हंगामे के तत्काल

अदालत में झूठ प्रमाणित होने के बाद क्या अब केजरीवाल अपनी सरकार का इस्तीफा लेंगे: सुधांशु त्रिवेदी

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 13 अगस्त।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर मीडिया को संबोधित किया और पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के निर्णय के बाद पंजाब सरकार पर न्यायालय में झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल से राज्य सरकार के इस्तीफे की मांग की।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने झारखंड और पंजाब के छात्रों के मुद्दों पर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल तथा जंतर-मंतर के कथित छात्र हितैषियों की चुप्पी पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि छात्र हितों का स्वांग रचने वालों का छात्रों के वास्तविक कष्टों से कोई सरोकार नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के कल के निर्णय के बाद एक बहुत गंभीर प्रश्न उठकर खड़ा हो गया है कि पंजाब में संसद



की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान विधानसभा पर पंजाब की सरकार ने झूठ बोला और यह न्यायालय में प्रमाणित हो गया। अब हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं, जो झारखंड से लेकर पंजाब तक के मामले पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए थे कि जब न्यायालय में आपकी सरकार का झूठ बोलना साबित हो गया है तो अब क्या आप अपनी सरकार का इस्तीफा लेंगे?

एलजी संधू का बड़ा विजन, द्वारका में बनेगा पांच सितारा होटल, 1,000 करोड़ से अधिक का निवेश

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 13 अगस्त।

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के द्वारका को प्रमुख आर्थिक, वाणिज्यिक और निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने के विजन के तहत क्षेत्र में एक और बड़ी परियोजना शुरू होने जा रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने द्वारका के सेक्टर-23 में पांच सितारा होटल विकसित करने के लिए जूनिपर होटल्स लिमिटेड की सहायक कंपनी जूनिपर



बादराज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

सत्र का औपचारिक समापन

दोनों सदनों के अनिश्चितकालीन स्थगन के साथ संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और विधेयक पारित होने के बावजूद आखिरी दिन भारी हंगामे के कारण सामान्य कार्यवाही नहीं हो सकी।

खरगे के अपमान पर प्रियंका ने जताया सख्त एतराज, मोदी से मांगा जवाब

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 13 अगस्त।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तराखंड में कांग्रेस की रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण के बाद मंच के शुद्धिकरण मामले पर कड़ा एतराज जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में जवाब मांगा है।

श्रीमती वाड्रा ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस तरह के कृत्य और ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा को दिखाती है।

इस तरह की सोच बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसी संकीर्ण मानसिकता को खारिज किया जाना चाहिए, यह क्या तरीका है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। श्री खरगे ने इसे खुद का और दलित समुदाय का अपमान बताया है और छुआछूत जैसा कृत्य

देश की सामूहिक स्मृति के संरक्षक और भविष्य की कल्पना के सृजक हैं कलाकार: मुर्मु

नई दिल्ली, यूटर्न/ 13 अगस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को यहां देश के प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए और कहा कि भारतीय परंपरा के वाहक ये कलाकार देश की सामूहिक स्मृति के संरक्षक और भविष्य की कल्पना के सृजक हैं।

रिजिजू ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया

नई दिल्ली, यूटर्न/ 13 अगस्त। संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने विपक्ष पर चर्चा से भागने आरोप लगाते हुए कहा कि यह पहली बार देखने को मिला जहां सरकार चर्चा कराना चाहती है जबकि विपक्ष चर्चा से भाग रही है। श्री रिजिजू ने मानसून सत्र की समाप्ति पर आज यहां पत्रकारों से कहा कि लोकसभा में कुल बारह विधेयक पारित किये गये जिनमें ग्यारह विधेयक बिना चर्चा के पारित किये गये। वहीं राज्य सभा में कुल बारह विधेयकों को चर्चा के बाद पारित किया गया। सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 19 प्रतिशत और राज्य सभा की उत्पादकता 39 प्रतिशत रही। उन्होंने कहा कि सत्र में चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं हैं क्योंकि विपक्ष खासकर कांग्रेस ने विधेयकों पर चर्चा नहीं करने दिया।



करार दिया है।

गुरुवार को इस मुद्दे पर राज्य सभा में काफी हंगामा हुआ और सदन के नेता जे पी नड्डा ने इस घटना की निंदा की और कार्रवाई का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि ऐसी खबरें हैं कि आठ अगस्त को हल्लानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में श्री खरगे के संबोधन के बाद मंच को धोया गया और शुद्धिकरण के लिए हवन किया गया।

हॉस्पिटैलिटी एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। यह समझौता 12 अगस्त 2026 को हुआ। डीडीए के उपाध्यक्ष एन. सरवण कुमार की मौजूदगी में हुए समझौते पर जूनिपर होटल्स लिमिटेड की ओर से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अरुण के. सराफ और अध्यक्ष अमित सराफ ने हस्ताक्षर किए।

इस परियोजना में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया जाएगा। होटल के निर्माण और संचालन से करीब 800 लोगों को

प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना शुल्क आधारित लाइसेंस व्यवस्था के तहत विकसित की जाएगी।

होटल के शुरू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में पांच सितारा आवास की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे कारोबार के सिलसिले में आने वाले लोगों, पर्यटकों और अन्य आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रस्तावित होटल की सबसे बड़ी खासियत इसकी रणनीतिक स्थिति होगी।

यह कर्तव्य है कि हम देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने में अपना योगदान दें। विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा थामे और 'भारत माता की जय' तथा 'वंदे मातरम' के गगनभेदी नारे लगाते हुए गाँव के मुख्य मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान नारों से पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया। इस सफल आयोजन के दौरान एनएसएस अधिकारी राजकुमार शास्त्री ने बताया कार्यक्रम में विद्यालय के अन्य अध्यापकगण सुरेंद्र कुमार, सुरेश कुमार, रामनिवास, राजेश कुमार, ओमप्रकाश, सुरेंद्र सिंह, सुनील कुमार, सुंदीप कुमार आदि सभी अध्यापक और सभी बच्चों ने बड़ चढ़कर भाग लिया।

सौ से ज्यादा मौतों के बाद सरकार की असली परीक्षा



संदीप शर्मा

देश के पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून एक बार फिर भारी तबाही लेकर आया है। लगातार बारिश और बाढ़ ने यह साफ कर दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं के सामने इंसानी तैयारियां भी कई बार बेबस नजर आती हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा सौ के पार पहुंच गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों परिवार प्रभावित हैं, सैकड़ों गांव जलमग्न हैं और सड़क, पुल, बिजली समेत कई जरूरी बुनियादी सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे हालात में सरकार के सामने राहत और बचाव के साथ-साथ प्रभावित लोगों के पुनर्वास और उनके सुरक्षित भविष्य की चुनौती भी है। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। राज्य के सात जिलों में करीब 1.37 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 456 गांव पानी में डूबे हुए हैं। बीते 24 घंटे में गोलाघाट और कार्बी आंगलों में दो और लोगों की मौत के बाद इस साल बाढ़ से जान गंवाने वालों की संख्या सौ से अधिक हो गई है। गोलाघाट सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है, जहां करीब 70 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके अलावा शिवसागर में लगभग 40 हजार और जोरहाट में 16 हजार से अधिक लोगों के प्रभावित होने की जानकारी है। राज्य की कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में हालात और चुनौतीपूर्ण होने की आशंका बनी हुई है। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र शुरू किए हैं। करीब 125 राहत शिविरों और राहत वितरण केंद्रों में लगभग 49 हजार लोगों तक सहायता पहुंचाई जा रही है। प्रशासन को प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने और जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय रखने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की यह सक्रियता जरूरी है, लेकिन इतनी बड़ी आपदा के बीच केवल मौके पर पहुंच जाना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। असली कसौटी यह है कि राहत अंतिम व्यक्ति तक कितनी तेजी और पारदर्शिता से पहुंचती है। बाढ़ केवल पानी का संकट नहीं होती। इसके साथ घर, खेत, पशुधन, रोजगार, सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य व्यवस्था भी प्रभावित होती है। जब पानी उतरता है, तब असली चुनौती शुरू होती है। लोगों के सामने घर दोबारा बनाने, खेती को पटरी पर लाने, बच्चों की पढ़ाई शुरू कराने और रोजी-रोटी का इंतजाम करने का संकट खड़ा हो जाता है। इसलिए असम सरकार की जिम्मेदारी राहत शिविर चलाने तक सीमित नहीं हो सकती। जिन लोगों ने अपना घर, जमीन, फसल या आजीविका गंवाई है, उनके पुनर्वास के लिए स्पष्ट और समयबद्ध योजना बनानी होगी। हिमाचल प्रदेश की स्थिति भी कम गंभीर नहीं है। 30 जून से शुरू हुए मानसून के दौरान बारिश से जुड़ी घटनाओं में 68 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 14 मौतें भूस्खलन और एक मौत फ्लैश फ्लड के कारण हुई है। राज्य को करीब 886 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। लगातार बारिश के कारण 106 सड़कें बंद हैं, जिनमें कुल्लू की 40 और मंडी की 38 सड़कें शामिल हैं। पहाड़ी राज्यों में सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि जीवनरेखा होती हैं। इनके बंद होने का अर्थ है कि गांवों तक खाद्य सामग्री, दवाइयां और दूसरी जरूरी वस्तुएं पहुंचाने में कठिनाई। मौसम विभाग ने मंगलवार को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में 16 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। ऐसे में प्रशासन को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चौकन्ना रहना होगा। संवेदनशील इलाकों में लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाना और बंद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलना जरूरी है। पहाड़ों में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। यह भी सच है कि प्राकृतिक आपदा को पूरी तरह रोक पाना किसी सरकार के हाथ में नहीं है। बादल कब फटेंगे, नदी कब उफनेगी या पहाड़ कब खिसकेगा, इसका सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं होता। लेकिन आपदा से होने वाले नुकसान को कम करना सरकार की जिम्मेदारी जरूर है। आधुनिक मौसम पूर्वानुमान, समय पर चेतावनी, मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र, सुरक्षित निकासी व्यवस्था और संवेदनशील इलाकों की पहचान के माध्यम से जनहानि को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यही कारण है कि अब सरकार की जवाबदेही केवल यह बताने तक सीमित नहीं होनी चाहिए कि कितने राहत शिविर लगाए गए और कितने लोगों को राहत सामग्री दी गई। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मृतकों के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा समय पर मिले, घायलों को उचित उपचार मिले, बेघर परिवारों को सुरक्षित आश्रय मिले और जिन लोगों की आजीविका नष्ट हुई है, उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। किसानों की फसल, मकानों, दुकानों और पशुधन को हुए नुकसान का निष्पक्ष आकलन कर मुआवजा दिया जाना चाहिए। असम और हिमाचल दोनों ही राज्यों में पुनर्वास सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। आपदा के बाद कई परिवार महीनों तक अस्थायी व्यवस्था में रहने को मजबूर हो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है और परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए पुनर्वास की प्रक्रिया कागजी घोषणाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। प्रभावित परिवारों की वास्तविक सूची तैयार कर सहायता सीधे उन तक पहुंचनी चाहिए। इसमें पारदर्शिता और निगरानी बेहद जरूरी है...

नेहरू-पटेल ने आजादी की जल्दी क्यों दिखाई?

एल एस हरदेनिया



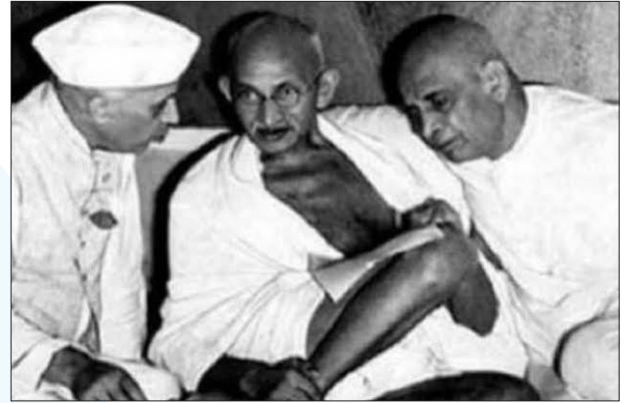
अब चूंकि ब्रिटेन अपना शासन समाप्त कर रहा था इसलिए देश के उन हिस्सों की सत्ता हिन्दुस्तान में कांग्रेस को सौंपी जाएगी और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग को सौंपी जाएगी जहां ब्रिटेन का सीधा शासन था। और जहां तक उन क्षेत्रों का सवाल है जहां राजा-महाराजा और नवाबों का शासन था, 15 अगस्त 1947 के बाद वे स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि वे स्वतंत्र नहीं रहना चाहते तो वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। यदि वे स्वतंत्र रहने का फैसला करते हैं तो आजाद भारत में सैकड़ों छोटे-छोटे देश अस्तित्व में आ जाएंगे।

भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती आई है कि भारत का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि नेहरूजी समेत सभी कांग्रेस नेता सत्ता का भोग करने को उतावले थे। यह कथन पूरी तरह से बेबुनियाद तो है ही, साथ ही इस बात का प्रतीक भी है कि जो लोग ऐसी बातें कहते हैं वे उस समय के घटनाक्रम से पूरी तरह अवगत नहीं हैं।

पहली बात यह है कि देश के आजाद होने के बाद जो पहली मंत्रिपरिषद बनी उसमें कांग्रेस नेताओं के अलावा अनेक गैर-कांग्रेसी भी शामिल किए गए थे। इनमें भाजपा के पूर्व अवतार जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे जो उस समय हिन्दू महासभा के प्रमुख नेता थे। मुखर्जी के अलावा डॉ अम्बेडकर को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था। चूंकि मंत्रिपरिषद का स्वरूप पूरी तरह से राष्ट्रीय था इसलिए यह कहना अनुचित है कि विभाजन इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि नेहरू को सत्ता हासिल करने की जल्दी थी।

मूल रूप से जून 1948 में अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे। इस बीच तत्कालीन वाईसराय माउंट बेटन लंदन गए। वे वहां से 3 जून 1947 को वापिस आए। वापिस आने के तुरंत बाद उन्होंने आल इंडिया रेडियो पर विभाजन की योजना घोषित की। अगले दिन माउंट बेटन ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने घोषणा की कि अब ब्रिटेन जून 1948 के स्थान पर 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर देगा। यह भी ज्ञात हुआ कि आजादी देने की तिथि में परिवर्तन करने का फैसला स्वयं माउंटबेटन का था।

इस तरह यह स्पष्ट है कि भारत के विभाजन की तिथि का निर्णय ब्रिटेन का था न कि नेहरू व अन्य कांग्रेस नेताओं का। माउंटबेटन की सोच थी चूंकि विभाजन का फैसला हो चुका है इसलिए उसका क्रियान्वयन करने में देरी न हो। यदि देरी होती है तो पूरे देश में साम्प्रदायिक हिंसा की आग फैल जाएगी। देरी के चलते लाखों लोग मारे जा सकते हैं।



शीघ्र आजाद करने का एक और प्रमुख कारण था। जैसा कि ज्ञात है कि हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों पर ब्रिटेन पर सीधा शासन था। वहीं कुछ हिस्सों पर ब्रिटेन ने राजा-महाराजाओं के माध्यम से शासन किया था।

अब चूंकि ब्रिटेन अपना शासन समाप्त कर रहा था इसलिए देश के उन हिस्सों की सत्ता हिन्दुस्तान में कांग्रेस को सौंपी जाएगी और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग को सौंपी जाएगी जहां ब्रिटेन का सीधा शासन था। और जहां तक उन क्षेत्रों का सवाल है जहां राजा-महाराजा और नवाबों का शासन था, 15 अगस्त 1947 के बाद वे स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि वे स्वतंत्र नहीं रहना चाहते तो वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। यदि वे स्वतंत्र रहने का फैसला करते हैं तो आजाद भारत में सैकड़ों छोटे-छोटे देश अस्तित्व में आ जाएंगे।

विभाजन को शीघ्र करने का एक और कारण देश का बालकेनाईजेशन रोकना था। ऐसे राजे-रजवाड़ों की संख्या 500 से ज्यादा थीं यदि ये सब आजाद होने का फैसला कर लेते तो भारत एक देश के रूप में अस्तित्व ले ही नहीं पाता। गांधी, नेहरू और पटेल इस बारे में पुख्ता निर्णय लेना चाहते थे। वे इस मामले में ठोस निर्णय चाहते थे। इसलिए इस गंभीर प्रश्न को लेकर नेहरू व पटेल 9 जुलाई 1947 को माउंटबेटन से मिले। उन्होंने माउंटबेटन से कहा कि वे इन राज्यों के भारत से संबंध के मुद्दे की समस्या को हल करने में क्या निर्णायक पहल कर सकते हैं। माउंटबेटन ने कहा कि वे स्वयं इस मामले को सुलझाना

चाहते हैं और यह उनके उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों में शामिल है।

उसी दिन इस मामले पर चर्चा के लिए गांधीजी भी माउंटबेटन से मिले। माउंटबेटन ने गांधीजी से हुई वार्ता को स्वयं रिकार्ड किया। गांधीजी ने कहा कि वे पूरी गंभीरता और दृढ़ता से इस मामले में निर्णय लें। वे यह सुनिश्चित करें कि राजे-महाराजे और नवाब स्वयं को आजाद घोषित न कर पाएं। माउंटबेटन ने इस संबंध में पूरी दृढ़ता से निर्णय लिया।

उन्होंने दिनांक 25 जुलाई को चेम्बर ऑफ प्रिन्सेस की बैठक बुलाई। माउंटबेटन ने कहा कि ब्रिटेन ने भारत की स्वतंत्रता के संबंध में बनाए गए कानून के द्वारा राजे-रजवाड़ों को ब्रिटेन से हर प्रकार से मुक्त कर दिया है। वे तकनीकी दृष्टि से पूरी तरह से आजाद हैं। ब्रिटेन से उनके सभी संबंध टूट गए हैं। यदि उनके स्थान पर नए संबंध नहीं बनाए जाते तो उसका नतीजा पूरी तरह अव्यवस्था और अराजकता होगा। इस अव्यवस्था का सीधा प्रभाव राज्यों पर पड़ेगा।

माउंटबेटन ने उन्हें सलाह दी कि वे नव निर्मित होने वाले उस देश से अपने संबंध स्थापित कर लें जिसके वे भौगोलिक दृष्टि से सबसे ज्यादा नजदीक हैं। आप अपने पड़ोसी देश से संबंध बनाए बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। उसी तरह आप अपनी प्रजा से दूर नहीं रह सकते हैं क्योंकि उसकी खुशहाली के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप अपनी प्रतिरक्षा स्वयं नहीं कर सकते।

ध्वजारोहण या ध्वज फहराना : 80वें स्वतंत्रता दिवस पर जानिए दोनों में फर्क

सुनील कुमार महला

15 अगस्त 2026 का दिन प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव, उत्साह और देशभक्ति का अवसर है। इस वर्ष हम भारत की स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ पूरी होने के बाद 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पाठक जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक क्षण राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा होता है। तिरंगा केवल तीन रंगों से बना एक ध्वज नहीं, बल्कि यह भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता, एकता, विविधता और असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। भारत का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। जब 15 अगस्त को तिरंगा आकाश में लहराता है, तो उसके साथ करोड़ों भारतीयों की आशाएं, आकांक्षाएं और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध भी जुड़ जाता है।

राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियमों में समय के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। 26 जनवरी 2002 से भारतीय ध्वज संहिता में बदलाव कर नागरिकों को अपने घर, कार्यालय और प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया। इससे पहले आम नागरिकों के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर कई प्रतिबंध थे। बाद में 30 दिसंबर 2021 के संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण में हाथ से काटे और हाथ से बुने कपड़ों के साथ-साथ मशीन से बने कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम और खादी के बटिंग के उपयोग



की अनुमति दी गई। इस प्रकार अब केवल खादी से बने ध्वज तक यह व्यवस्था सीमित नहीं रही। इसके बाद 20 जुलाई 2022 को भारतीय ध्वज संहिता में एक और महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। इसके तहत किसी नागरिक के घर पर राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात दोनों समय फहराने की अनुमति दी गई। इसलिए सूर्यास्त के बाद घर पर तिरंगा उतारना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, रात में ध्वज फहराते समय उसकी गरिमा और सम्मान का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। राष्ट्रीय ध्वज साफ-सुथरा, सही स्थिति में और सम्मानजनक एवं प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित होना चाहिए। केसरिया पट्टी हमेशा ऊपर की ओर होनी चाहिए और ध्वज उल्टा नहीं लगाया जा सकता। ध्वज फटा, मैला या अस्त-व्यस्त नहीं होना चाहिए तथा उसे जमीन, फर्श या पानी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग सजावट, झालर, बटिंग आदि के रूप में नहीं किया जा सकता। आज अधिकार और जनभागीदारी की भावना को आगे बढ़ाते हुए 'हर घर तिरंगा' अभियान के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और

राष्ट्रभक्ति व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह अभियान तिरंगे को केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित रखने के बजाय प्रत्येक नागरिक के घर और जीवन से जोड़ने का माध्यम बना है।

हालांकि, यहां यह समझना भी जरूरी है कि 'ध्वजारोहण' और 'ध्वज फहराना' शब्दों का प्रयोग अक्सर एक-दूसरे के स्थान पर कर दिया जाता है, लेकिन इनके अर्थ और परंपरागत प्रयोग में अंतर है। ध्वजारोहण का शाब्दिक अर्थ है-ध्वज को नीचे से ऊपर उठाकर निर्धारित ऊंचाई तक ले जाना और स्थापित करना। वहीं ध्वज फहराने का आशय है-पोल के ऊपर स्थित ध्वज को खोलकर अथवा फैलाकर हवा में लहराना। इस दृष्टि से दोनों क्रियाओं की प्रकृति अलग है। भारत के राष्ट्रीय पर्वों में इस अंतर को समझने के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी का उदाहरण सबसे उपयुक्त है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इसके विपरीत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण करते हैं। इसलिए सामान्यतः कहा जाता है कि 15 अगस्त को ध्वज फहराया जाता है और 26 जनवरी को ध्वजारोहण किया जाता है। इसके पीछे दोनों राष्ट्रीय पर्वों की ऐतिहासिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। उस समय ब्रिटिश शासन के प्रतीकात्मक रूप से हटने और स्वतंत्र भारत के उदय का संदेश देते हुए तिरंगे को ऊपर फहराया गया। दूसरी ओर, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और देश एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना।

सरकार लाएगी मल्टीलिंगुअल एआई, अब अपनी भाषा में मिलेगी सरकारी सेवाएं

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 13 अगस्त

केन्द्र सरकार मल्टीलिंगुअल और वॉयस-फर्स्ट एआई तकनीक पर काम कर रही है ताकि शासन और सार्वजनिक सेवाएं ज्यादा समावेशी और आसान बन सकें। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, इस लक्ष्य के लिए डिजिटल इंडिया 'भाषिणी' डिवीजन डीआईबीडी और नीति आयोग ने भाषिणी फॉर सेवा/संचालन पहल के तहत एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का मकसद 'भाषिणी' के मल्टीलिंगुअल एआई इकोसिस्टम का इस्तेमाल करके शासन को ज्यादा समावेशी और सुलभ बनाना है। इसके लिए नीति आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवाओं में एआई आधारित भाषा तकनीकों को जोड़ा जाएगा।

सरकारी बयान में कहा गया, 'यह साझेदारी नागरिकों को उनकी पसंदीदा भारतीय भाषाओं में सरकारी जानकारी



और सेवाओं तक पहुंच दिलाएगी। इससे सरकार और नागरिकों के बीच संवाद मजबूत होगा और सार्वजनिक सेवा वितरण में बहुभाषी संचालन को बढ़ावा मिलेगा।' इस साझेदारी के तहत 'भाषिणी' के भाषा अनुवाद एपीआई और रेफरेंस एप्लीकेशन के जरिए नीति आयोग की सेवाओं तक बहुभाषी पहुंच आसान होगी। इसके साथ ही अनुवाद मॉडल के विकास और लगातार सुधार

में मदद मिलेगी। भाषा तकनीकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और संचार वर्कफ्लो में भी जोड़ा जाएगा। इस इको सिस्टम का एक अहम हिस्सा 'स्मृति' है। इसका पूरा नाम सिस्टम फॉर मीटिंग रिकॉर्डिंग, इनफॉर्मेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इंटरफेस है। इसे 'भाषिणी' के साथ मिलकर विकसित किया गया है। 'स्मृति' बैठक के मिनट्स को अपने आप तैयार करेगा

और उनका बहुभाषी अनुवाद भी करेगा। इससे सरकारी कामकाज की दक्षता बढ़ेगी और अंतिम व्यक्ति तक शासन ज्यादा समावेशी बनेगा। यह सहयोग नीति आयोग के 'नीति तारा' यानी टूलकिट फॉर एनालिसिस, रिव्यू एंड एक्शन पर भी आधारित है। 'नीति तारा' डेटा को जमीनी स्तर पर कार्रवाई में बदल रहा है।

अब तक देशभर में 200 से ज्यादा क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। इनके जरिए जिलों और ब्लॉकों के 4,000 से अधिक अधिकारियों को डेटा आधारित अंतर्दृष्टि के लिए प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे साक्ष्य आधारित फैसले ले सकें।

साझेदारी के तहत नीति आयोग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रेफरेंस एप्लीकेशन और वॉयस बॉट भी विकसित किए जाएंगे। साथ ही विशेष शब्दावली और क्षेत्र विशेष की जरूरतों के लिए भाषा तकनीक को मजबूत किया जाएगा।

2027 तक ऑडी लॉन्च करेगी 3 नई लगजरी एसयूवी

नई दिल्ली, यूटर्न/ 13 अगस्त । वर्ष 2027 तक ऑडी भारतीय लगजरी कार बाजार में तीन महत्वपूर्ण एसयूवी मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिनमें क्यू6 ई-ट्रॉन ईवी, नई क्यू5 और नई क्यू7 शामिल हैं। ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह दिल्ली ने इन योजनाओं की पुष्टि की है। क्यू6 ई-ट्रॉन ईवी ऑडी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी जिसे भारत में स्थानीय स्तर पर तैयार किया जाएगा। यह पोश के साथ विकसित 800 वोल्ट के प्रीमियम प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर आधारित है और इसमें लगभग 100 किलोवाट-घंटे की बैटरी के साथ 641 किलोमीटर तक की दावा की गई दूरी मिल सकती है। इसके केबिन में 11.9 इंच का डिजिटल चालक प्रदर्शन, 14.5 इंच की केंद्रीय स्पर्श स्क्रीन और सामने बैठे यात्री के लिए 10.9 इंच की अतिरिक्त स्क्रीन जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी वर्ष 2027 के मध्य में लगभग 85 लाख रुपये की अनुमानित कीमत पर आ सकती है। इसके बाद, नई पीडी की क्यू5 अक्टूबर 2027 तक लगभग 75 लाख रुपये की अनुमानित कीमत पर लॉन्च होने की उम्मीद है। यह तीसरी पीढ़ी की एसयूवी नए पीपीसी ढांचे पर आधारित होगी, जिसमें 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और आधुनिक केबिन डिजाइन मिलेगा। अंत में, नई क्यू7 दिसंबर 2027 तक लगभग 1.20 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत पर आएगी।

एवोर ने अपनी नई इलेक्ट्रिक

बाइक श्रृंखला पेश की

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 13 अगस्त ।

गुजरात की वाहन निर्माता कंपनी एवोर ने अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक श्रृंखला पेश की है, जिसमें ईएक्स1, ईएक्स2 और ईएक्स2एस जैसे तीन मॉडल शामिल हैं। एवोर की इस श्रृंखला का सबसे खास मॉडल ईएक्स2एस है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज होने पर 260 किलोमीटर तक की प्रभावशाली दूरी तय कर सकती है। इसमें 5 किलोवाट-घंटे क्षमता वाली बड़ी बैटरी और 114 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति मिलती है।

ईएक्स2एस में आधुनिक 7 इंच की स्पर्श स्क्रीन और पांच अलग-अलग चलाने के तरीके भी दिए गए हैं, जिसकी शुरुआती कीमत 1.70 लाख रुपये है। श्रृंखला के शुरुआती मॉडल ईएक्स1 में 3.24 किलोवाट-घंटे की बैटरी के साथ 160 किलोमीटर की दूरी और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति मिलती है, जिसकी कीमत 1.23 लाख रुपये है। वहीं, ईएक्स2 मॉडल 5 किलोवाट-घंटे की बैटरी के साथ 255 किलोमीटर की दूरी और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्रदान करता है, जिसकी कीमत 1.46 लाख रुपये है।

एवोर की ये लंबी दूरी वाली इलेक्ट्रिक बाइक ओला और एथर जैसी स्थापित कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकती हैं, जो मुख्य रूप से स्कूटर बाजार में मजबूत हैं। कंपनी का यह कदम उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है जो स्कूटर के बजाय मोटरसाइकिल जैसा अनुभव और लंबी दूरी चाहते हैं। कंपनी ने इन बाइक्स की अग्रिम बुकिंग केवल 799 रुपये में शुरू कर दी है, जिससे ग्राहकों के लिए यह एक आकर्षक विकल्प बन सकती है।

संक्षिप्त खबरें

सरकार का ईवी पर जोर, ऑटो पीएलआई प्रोत्साहन दोगुना होगा

नई दिल्ली, यूटर्न/ 13 अगस्त । भारी उद्योग मंत्रालय देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और उन्नत ऑटोमोबाइल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय है। मंत्रालय को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026-27 में ऑटोमोबाइल उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत लगभग 4,700 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो पिछले दो वर्षों (2,322 करोड़ रुपये) में दिए गए कुल प्रोत्साहन से दोगुना से भी अधिक है। इसके साथ ही, मंत्रालय ई-बस और ई-ट्रक जैसे भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए वित्तपोषण में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए एक नई वित्तीय व्यवस्था पर भी विचार कर रहा है, जिसमें ब्याज सब्सिडी देने का प्रस्ताव शामिल है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अनुमानित 4,700 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि में से लगभग 700 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं, शेष राशि आने वाले महीनों में जारी होगी। ऑटोमोबाइल पीएलआई योजना, जिसका कुल परिव्यय 25,938 करोड़ रुपये है, का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों और उन्नत ऑटोमोबाइल तकनीक से जुड़े पुर्जों (जैसे ट्रेक्शन मोटर और एंगल एनकोडर) बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहित करना है। योजना की अवधि बढ़ाकर अब वित्त वर्ष 2028-29 तक कर दी गई है।

2027 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेगी हीरो मोटोकॉर्प

नई दिल्ली, यूटर्न/ 13 अगस्त । दो पहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प कंपनी वर्ष 2027 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेगी। कंपनी का ध्यान अभी तक मुख्य रूप से विंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर तक सीमित था, लेकिन अब वह इलेक्ट्रिक बाइक श्रेणी में प्रवेश कर रही है। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी इसके लिए दो बिल्कुल नए बाइक-विशेष प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है, जिनके नाम यूबीईएक्स और वीएक्सजेड हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ये नए प्लेटफॉर्म मौजूदा विंडा स्कूटर के ढांचे पर आधारित नहीं होंगे, बल्कि इन्हें विशेष रूप से बाइक की बेहतर सवारी, प्रदर्शन और चढ़ाई की क्षमता को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। यूबीईएक्स प्लेटफॉर्म शहरी और स्पोर्टी बाइक के लिए होगा, जबकि वीएक्सजेड को ज्यादा दमदार और साहसिक यात्राओं के लिए विकसित किया जा रहा है। वीएक्सजेड परियोजना में हीरो मोटोकॉर्प अमेरिकी कंपनी जीरो मोटरसाइकिल्स के साथ सहयोग कर रही है।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में 440 स्टार्टअप सक्रिय , 18 स्टार्टअप्स को इन-स्पेस से मिली मंजूरी : सरकार

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 13 अगस्त ।

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है और निजी कंपनियों तथा स्टार्टअप्स की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। केन्द्र सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि देश में वर्तमान में लगभग 440 स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं। इसके साथ ही भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनियां अगले दो वर्षों के दौरान आठ से अधिक वाणिज्यिक रॉकेट लॉन्च कर सकती हैं, जो देश के उभरते अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।

राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर करीब 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं। यह संख्या दर्शाती है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और निजी निवेश तेजी से बढ़ रहा है।

मंत्री ने कहा कि इन-स्पेस यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (आईएन-एसपीएसीई) ने अब तक 52 गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकृत मंजूरियां प्रदान की हैं, जिनमें से 18 कंपनियां स्टार्टअप्स हैं, जिन्हें भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम का अग्रणी माना जा रहा है। इन स्टार्टअप्स में अग्निकुल कॉसमॉस, बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस, ध्रुवा स्पेस, दिगंतारा



रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, गैलेक्सीआई स्पेस सॉल्यूशंस, मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजीज, पिक्सल स्पेस इंडिया, स्काईरूट एयरोस्पेस और स्पेस किड्स इंडिया जैसी कंपनियां शामिल हैं।

इसके अलावा अक्षत एयरोस्पेस, अजिस्ता बीएसटी, कॉसमोसर्व स्पेस इंडिया, हेक्स20 लैम्ब्स इंडिया, इनऑर्बिट स्पेस टेलीकम्युनिकेशंस, एनस्पेस टेक इंडिया, ऑर्बिटएड एयरोस्पेस, पियरसाइट स्पेस और टेकमी2स्पेस टेक्नोलॉजीज को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने बताया कि इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड्स, के उपयोग के लिए आने वाले आवेदनों को निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया

(एसओपी) के तहत मंजूरी दी जाती है। इन-स्पेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का विशेषज्ञ समिति द्वारा तकनीकी और परिचालन तैयारी के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

निजी क्षेत्र की रॉकेट लॉन्च गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान दो निजी रॉकेट लॉन्च प्रस्तावित हैं। वहीं वित्त वर्ष 2027-28 के लिए लॉन्च कार्यक्रम को अभी अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन उस वर्ष भारतीय निजी कंपनियों द्वारा छह से अधिक रॉकेट लॉन्च किए जाने की संभावना है। सरकार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए बड़े पैमाने पर खोल दिया है।

अमेरिका का क्रिप्टो कानून, भारत के वीडिए नियमन को नई दिशा

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 13 अगस्त ।

अमेरिका की संसद के उच्च सदन सीनेट में एक महत्वपूर्ण क्रिप्टोकॉरेसी विधेयक, डिजिटल एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट को आगे बढ़ाने के कदम ने भारत में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों (वीडीए) को विनियमित करने की कोशिशों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है। यह घटनाक्रम भारत की संसदीय समिति द्वारा हाल ही में वीडिए विनियमन में अंतर पाटने के लिए कानूनी प्रारूप की मांग के कुछ सप्ताह बाद आया है, जिससे वैश्विक नियामक स्पष्टता की दिशा में एक अहम बहस छिड़ गई है। अमेरिकी सीनेट में बहुमत दल के नेता जॉन थ्यून ने पिछले दिनों इस विधेयक पर आगे की बहस समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया, जिससे 15 सितंबर को होने वाले प्रक्रियात्मक मतदान का रास्ता साफ हो गया है। यह विधेयक इससे पहले



अमेरिका के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में दोनों दलों के समर्थन से पारित हो चुका है (संभवतः जुलाई 2024 में)। डिजिटल एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट का प्राथमिक उद्देश्य डिजिटल कमोडिटी के लिए एक स्पष्ट नियामक ढांचा बनाना और सिक्नोरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) व कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) के अधिकार-क्षेत्र को स्पष्ट करना है।

2026 में 50 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ने की राह पर भारत, घरेलू सप्लाई चेन को मजबूती देने वाली नीतियों से बड़ी रफ्तार

नई दिल्ली, यूटर्न/ 13 अगस्त । भारत वर्ष 2026 में सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि का नया रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। वुड मैकेजी की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वर्ष 2026 की पहली छमाही (जनवरी-जून) में 34 गीगावाट डायरेक्ट करंट (जीडब्ल्यूडीसी) सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 38 प्रतिशत अधिक है। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए पूरे वर्ष में भारत 50 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ सकता है, जो देश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक विस्तार होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत इस वर्ष अपने सौर ऊर्जा स्थापना इतिहास में किसी भी अन्य वर्ष की तुलना में सबसे अधिक क्षमता स्थापित करने जा रहा है। हालांकि, इस तेज वृद्धि को बढ़ावा देने वाली नीतियां घरेलू सप्लाई चेन पर दबाव भी पैदा कर रही हैं, जिसके चलते निकट अवधि में सौर परियोजनाओं की लागत बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार, डेवलपर्स ने मॉडल और निर्माताओं की स्वीकृत सूची-II (एएलएमएम-II) की जून 2026 समयसीमा से पहले परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का प्रयास किया। इसी वजह से वर्ष की पहली छमाही में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण और कमीशनिंग में उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली। वुड मैकेजी के रिसर्च एनालिस्ट सुरीत सिंह ने कहा कि एएलएमएम-क्वार्टर भारत में पूरी तरह एकीकृत घरेलू सौर सप्लाई चेन विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता की तुलना में देश में सौर सेल निर्माण क्षमता अभी पर्याप्त गति से नहीं बढ़ पाई है। उनके अनुसार, निकट अवधि में लागत बढ़ना लगभग तय है और डेवलपर्स को कीमतों के स्थिर होने तक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पड़ सकता है।

संक्षिप्त खबरें

साइकिल सवार की ट्रक की टक्कर से मौत, एक घंटे तक नहीं पहुंची एंबुलेंस

फरीदाबाद, यूटर्न/ 13 अगस्त । सेक्टर-25 में भारत धर्मकांटा के सामने बुधवार दोपहर करीब तीन बजे ट्रक की टक्कर से करीब 60 वर्षीय साइकिल सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भाग गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद करीब एक घंटे तक एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। इस दौरान डायल-112 की गाड़ी मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि साइकिल सवार कोल्ड ड्रिंक लेने आया था। उसकी साइकिल की कैरियर पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी रखी थी। इसी दौरान ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक राहगीर ने ट्रक की नंबर प्लेट का फोटो ले लिया था, जिसे पुलिस को भेजा गया है। पुलिस ने शव की तलाशी ली, लेकिन उसके पास से पहचान संबंधी कोई दस्तावेज या अन्य साक्ष्य नहीं मिला। मृतक की उम्र करीब 60 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने शव को ईएसआई अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मृतक की पहचान के लिए इशतहार जारी कर प्रयास किए जा रहे हैं। पहचान होने के बाद परिजनों से लिखित शिकायत ली जाएगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ट्रक की नंबर प्लेट के आधार पर चालक की तलाश कर रही है।

होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर युवक की मौत

गाजियाबाद, यूटर्न/ 13 अगस्त । नगर कोतवाली क्षेत्र के बजरिया स्थित इंदर होटल में मंगलवार रात रुके बिहार निवासी युवक की बुधवार सुबह तीसरी मंजिल की बालकनी से गिरकर मौत हो गई। गंभीर हालत में होटल स्टाफ उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। एसीपी नगर कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि ग्राम जरौली, पोस्ट हरियाली, थाना निर्मली, सुपौल (बिहार) निवासी आलोक राय (36) मंगलवार शाम दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से अपने जीजा ललित कामत से मिलने बजरिया पहुंचे थे। ललित कामत मूलरूप से ग्राम झिटकी, थाना नरहिया, मधुबनी (बिहार) के रहने वाले हैं और वर्तमान में कोटगांव, यादव नगर में रहते हैं। वह बजरिया स्थित इंदर होटल में मैनेजर हैं। ललित कामत ने आलोक को रात में होटल की तीसरी मंजिल स्थित गेस्ट रूम में ठहरने के लिए कहा था। एसीपी के मुताबिक आलोक की बहन का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उपचार चल रहा है।

लैंडक्राफ्ट सोसायटी की 25वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत

गाजियाबाद, यूटर्न/ 13 अगस्त । कविनगर की लैंडक्राफ्ट सोसायटी के टॉवर-2ए की 25वीं मंजिल से गिरकर बुधवार को 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान न्यू पंचवटी निवासी अर्पण गोयल के रूप में हुई। पुलिस प्रथमदृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है। अर्पण अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे और नोएडा की इनोवेटिव व्यू कंपनी में नौकरी करते थे।

एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि सुबह करीब नौ बजे डायल 112 के माध्यम से सोसायटी में अर्पण के गंभीर हालत में पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस उनको संजयनगर स्थित जिला संयुक्त अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस की शुरूआती जांच में सामने आया कि अर्पण के दोस्त प्रखर का फ्लैट सोसायटी के टॉवर-2ए की 14वीं मंजिल पर है। अर्पण सुबह उनसे मिलने सोसायटी पहुंचे और फोन किया। प्रखर ने उन्हें बताया कि वह फ्लैट पर मौजूद नहीं हैं। इसके बाद अर्पण 25वीं मंजिल पर पहुंचे और वहां से नीचे गिर गए। एसीपी ने बताया कि सोसायटी के गेट और लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में अर्पण अकेले 25वीं मंजिल की ओर जाते दिखाई दिए हैं। उनके दोस्त का फ्लैट 14वीं मंजिल पर था, लेकिन अर्पण लिफ्ट से सीधे 25वीं मंजिल पर पहुंचे।



पुलिस के मुताबिक, वह गिरल की ओर गए और वहां से नीचे गिर गए। सोसायटी के कुछ लोगों ने बताया कि अर्पण की सोसायटी में रहने वाले एक युवक से कहासुनी हुई थी। इसके बाद वह मोबाइल फोन पर किसी से आक्रोशित होकर बात कर रहे थे। कुछ लोगों ने उनके शोर मचाने की आवाज भी सुनी थी। इसके बाद एक घरेलू सहायिका ने अर्पण को गंभीर हालत में जमीन पर पड़ा देखा। एसीपी के मुताबिक, अर्पण की जेब से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उनके माता-पिता ने भी किसी से रंजित होने से इन्कार किया है। उन्होंने बताया कि बेटे की शादी के लिए युवती की तलाश की जा रही थी।

बच्चों की तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार



» गाजियाबाद, यूटर्न/ 13 अगस्त ।

टीला मोड़ थाना पुलिस ने बच्चों को अगवा कर निसंतान दंपतियों को चार से पांच लाख रुपये में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दो महिलाओं समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह ने नौ अगस्त को टीला मोड़ की करन गेट चौकी के पास किराये के मकान में रहने वाली मुस्कान के चार माह के बेटे अल्लाबरखा को अगवा कर शामली के एक दंपती से उसका पांच लाख रुपये में सौदा किया था। पुलिस ने बच्चे को सकुशल उसके माता-पिता को सौंप दिया है।

डीसीपी सिटी व ट्रांस हिंडन धवल जायसवाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मूलरूप से बिहार और हाल में पानीपत की पंडित कॉलोनी निवासी ऐनुल (35), मुजफ्फरनगर निवासी नौशाद (36), उसकी पत्नी रुखसार (32), मुजफ्फरपुर बिहार

निवासी नागेंद्र उर्फ सुक्का (40), शामली के कैराना निवासी नसीम (38), आर्दश मंडी शामली निवासी आबिद (40) और किशनगंज बिहार निवासी सुमित्रा (58) शामिल हैं। डीसीपी के अनुसार, गिरोह का सरगना नौशाद है।

निकाह की तैयारियों के बीच गायब हुआ मासूम

अल्लाबरखा के पिता फुरकान और माता मुस्कान ने बताया कि वे मूलरूप से अकराबाद थाना क्षेत्र के कौड़ियागंज, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। करीब ढाई वर्ष से करन गेट चौकी के सामने किराये के मकान में रहकर मजदूरी करते हैं। उनके तीन बच्चे कबीर (5), फरहान (3) व अल्लाबरखा हैं। आरोपी नौशाद और उसकी पत्नी रुखसार भी इसी मकान में करीब ढाई माह से किराये पर रहते थे। दोनों कूड़ा बीनकर उसे बेचने का काम करते थे। नौ अगस्त को फुरकान के छोटे भाई शमसुद्दीन का निकाह था। घर में निकाह की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान रुखसार अपनी बेटी के साथ उनके घर पहुंची और अल्लाबरखा को खिलाने के बहाने साथ ले गईं। काफी देर तक बच्चा नहीं लौटा तो परिजनों ने रुखसार से पूछताछ की। उसने बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी होने से इन्कार कर

दिया और वहां से चली गईं।

ऐनुल ने कराया था सौदा

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि करीब डेढ़ वर्ष पहले आरोपी नौशाद और ऐनुल सोनीपत की एक फैक्टरी में साथ काम करते थे। वहीं दोनों में दोस्ती हुई। ऐनुल हरियाणा में कमीशन पर शादियां भी कराता था। हाल में ऐनुल ने नौशाद और रुखसार को बताया था कि शामली के कांथला निवासी नफीस व उसकी पत्नी मौसीना निसंतान हैं। उनको बच्चा उपलब्ध कराने पर पांच लाख रुपये मिलेंगे। मौका मिलने पर रुखसार ने बच्चे को अगवा कर लिया। इसके बाद आरोपी दंपती बच्चे को लेकर शामली पहुंच गए, लेकिन बच्चे को सौंप जाने से पहले ही मंगलवार को पुलिस ने उनको दबोच लिया। नौशाद व रुखसार से पूछताछ में अन्य आरोपियों के बारे में पता चला, जिसके बाद उनको भी अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, बच्चे को खरीदने वाली मौसीना और इसमें उसका सहयोग करने वाली सितारा फरार है। उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस पूछताछ में नौशाद ने बताया कि करीब डेढ़ वर्ष पहले उसने अपनी पत्नी की कोख में पल रही बच्ची का जन्म से पहले ही सोनीपत के एक निसंतान दंपती से 2.40 लाख रुपये में सौदा कर लिया था।

स्कूल जाते समय चार साल के बच्चे पर कुत्तों ने किया हमला

गाजियाबाद, यूटर्न/ 13 अगस्त । मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में बुधवार सुबह स्कूल जा रहे चार वर्षीय बच्चे पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्चे को जमीन पर गिराकर शरीर के कई हिस्सों पर बुरी तरह नोच लिया। हमले में बच्चे के शरीर पर करीब दस जगह गंभीर घाव हुए हैं। संयुक्त अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को बेहतर इलाज और प्लास्टिक सर्जरी के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। संयुक्त अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार नाहल गांव निवासी अनीस का चार वर्षीय बेटा अमन गांव के सना पब्लिक स्कूल में केजी कक्षा में पढ़ता है। बुधवार सुबह अमन अपने दो साथियों के साथ स्कूल जाने के लिए घर से निकला था। रास्ते में आवारा कुत्तों का झुंड देखकर उसके दोनों साथी डरकर वापस भाग गए, लेकिन अमन उनके साथ नहीं जा सका। इसी दौरान कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्चे को जमीन पर गिराकर शरीर के कई हिस्सों में काट लिया। बच्चे की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्तों को भगाकर उसे बचाया। परिजन घायल बच्चे को तत्काल संयुक्त अस्पताल लेकर पहुंचे।

पर्वतीय कॉलोनी में सात दिन से पानी की किल्लत

फरीदाबाद, यूटर्न/ 13 अगस्त । पर्वतीय कॉलोनी में पिछले सात दिनों से लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। घरों में नलों के माध्यम से गंदा और बदबूदार पानी पहुंच रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सीवर का पानी पेयजल लाइन में मिलकर आ रहा है। इससे लोगों में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। समस्या के समाधान के लिए शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में रोष है।

स्थानीय निवासी मधू और शिवम के अनुसार, गंदा पानी आने के कारण उसका इस्तेमाल घरेलू कार्यों में भी नहीं किया जा रहा है। खाना बनाने, कपड़े धोने और अन्य जरूरी कामों के लिए लोगों को साफ पानी की व्यवस्था अलग से करनी पड़ रही है। मजबूरी में कई परिवार टैंकर मंगवाकर पानी भरवा रहे हैं। इससे लोगों की परेशानी के साथ-साथ आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है।

समस्या के समाधान की मांग की

स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजमर्रा के कामों के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है, जिससे घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। वहीं, दूषित पानी के लगातार इस्तेमाल से बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर भी परिवार चिंतित हैं। निवासियों ने संबंधित विभाग से पेयजल लाइन की जांच कराने और सीवर का पानी उसमें मिस होने की समस्या को तत्काल दूर करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि सात दिन बीतने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने जल्द स्वच्छ पेयजल आपूर्ति बहाल करने और स्थायी समाधान कराने की मांग की है।

आरपीएफ ने 10 लोगों से वसूला 13,500 रुपये का जुर्माना

फरीदाबाद, यूटर्न/ 13 अगस्त । स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की ओर से ट्रेनों और रेलवे स्टेशन परिसर में चेंकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को आरपीएफ/एफडीबी की टीम ने गाड़ी संख्या 64903 ईएमयू (मथुरा-गाजियाबाद) के महिला कोच की जांच की। इस दौरान महिला कोच में यात्रा कर रहे चार पुरुष यात्रियों को पकड़ा गया।

आरपीएफ ने चारों के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 162(एक) के तहत कार्रवाई की। इनमें नरनिश (29), राजेंद्र सिंह (56), बिट्टू कुमार (25) और मनीष कुमार (19) शामिल हैं। चारों से 2500-2500 रुपये जुर्माना वसूला गया।

इसके अलावा रेलवे लाइन पार करते पांच लोगों को पकड़ा गया। इनके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 147(एक) के तहत कार्रवाई की गई। इनमें पंकज कुमार (37), वीरेंद्र (34), भीम (26), संदीप (24) और राहुल (25) शामिल हैं। सभी से 500-500 रुपये जुर्माना लिया गया।

वहीं, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने और रेलवे लाइन पार करने के मामले में आरोही (26) को पकड़ा गया। उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 159 और 147 के तहत कार्रवाई करते हुए 1000 रुपये जुर्माना वसूला गया। चेंकिंग अभियान में कुल 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सभी मामलों में कुल 13,500 रुपये जुर्माना वसूला गया।

रेल हादसों ने छीना मां का पूरा संसार, पति-बेटे के बाद बेटी भी गई

» फरीदाबाद, यूटर्न/ 13 अगस्त

नीलम पुल के पास बुधवार सुबह रेलवे लाइन पार करने के लिए शॉर्टकट रास्ता लेना एक छात्रा का अंतिम सफर बन गया। तेज रफ्तार गतिमान एक्सप्रेस की चपेट में आने से 11वीं कक्षा की छात्रा तानिया (17) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना सुबह करीब 8:30 बजे जीआरपी पहुंची। ट्रेन के इंजन के अगले हिस्से में छात्रा का शव फंसा था, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि घटनास्थल पर परिजनों ने शव की शिनाख्त की। इसके बाद जीआरपी ने शव का पंचनामा भरा और उसे



पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल के शवगृह में भिजवा दिया गया है।

शुरूआती जांच के अनुसार तान्या स्कूल पहुंचने की जल्दबाजी में नीलम पुल के पास से रेलवे लाइन पार कर रही

शॉर्टकट बना अंतिम सफर... गतिमान एक्सप्रेस ने थामी छात्रा की सांसें

थी। इसी दौरान तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। रेलवे ने लोगों को पटरियों से गुजरने से रोकने के लिए वहां पक्की दीवार भी बनाई हुई है, लेकिन तान्या जान जोखिम में डालकर लाइन पार

करने लगी और हादसा हो गया। पटरियों पर उसकी किताबें और स्कूल बैग बिखरा पड़ा था। पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली, तो उसमें से किताबें और एक पर्ची पर लिखा मोबाइल नंबर मिला। उसी नंबर पर संपर्क कर जीआरपी ने तान्या के परिजनों को हादसे की सूचना दी, जिसके बाद परिजन रोजे-बिलखते मौके पर पहुंचे।

जब तान्या की मां सुदेश (45) बदहवास हालत में मौके पर पहुंचीं, तो वहां का दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। घरों में झाड़ू-पोछा करके पाई-पाई जोड़ने वाली मां अपनी इकलौती बच्ची संतान के बैग और कपड़ों को देखकर बेसुध होकर गिर पड़ीं।

सभी गोल्फरों को आईजीपीएल में खेलने की अनुमति दी जाये: जीव

सभी खिलाड़ियों को अच्छी कमाई का अधिकार मिले

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 13 अगस्त ।

देश के शीर्ष गोल्फरों में शामिल जीव मिल्खा सिंह ने कपिल देव के नेतृत्व वाली इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (आईजीपीएल) से अपील की है कि वह सभी गोल्फरों को इस नई लीग में भाग लेने का अवसर दे। जीव के अनुसार सभी खिलाड़ियों को अच्छी कमाई करने और अपने खेल को बेहतर बनाने का अवसर मिलना चाहिये। जीव ने से अपील इसलिए की है क्योंकि भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर (पीजीटीआई) ने आईजीपीएल में खेलने वाले गोल्फरों के अपनी प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर रोक लगा दी है जिससे गोल्फरों के सामने संशय बना हुआ है।

जीव ने माना है हर टूर के अपने अलग नियम और खिलाड़ियों से की जाने वाली प्रतिबद्धताएं होती हैं पर उन्होंने कहा कि एक बार जब कोई खिलाड़ी अपने प्राथमिक टूर के प्रति अपनी सभी निर्धारित प्रतिबद्धताओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, तो उसे अन्य रास्तों और व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने से रोकना सही नहीं है। जीव के अनुसार, आपके दो या तीन टूर (गोल्फ टूर्नामेंट) हो सकते हैं, पर अंत में यह खिलाड़ियों के टूर हैं। अगर उन्हें इससे फायदा हो रहा है तो इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगर वे इससे अच्छी कमाई



कर सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। उनका स्पष्ट मानना है कि खिलाड़ियों के हित और उनके करियर का विकास ही सर्वोपरि होना चाहिए। वहीं इस पूरे विवाद के केंद्र में हाल में गठित आईजीपीएल है उसके जिसके सह-संस्थापकों में एक अन्य विश्व कप विजेता क्रिकेटर, युवराज सिंह भी शामिल हैं। वहीं पीजीटीआई ने आईजीपीएल में भाग लेने वाले गोल्फरों को अपनी प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी है। वहीं आईजीपीएल के प्रमुख कपिल देव ने इस स्थिति पर अपनी राय रखते हुए स्वीकार किया है कि दोनों के ही टूर्नामेंट साथ-साथ आयोजित किए जा सकते हैं पर उन्होंने इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि खिलाड़ियों को इन दोनों लीगों में से किसी एक को चुनना होगा।

अरशद नदीम का फोकस एशियन गेम्स पर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे दक्षिण अफ्रीका

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 13 अगस्त ।

पेरिस ओलंपिक 2024 में जैवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। वह नौवें स्थान पर रहे थे। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद किसी को नहीं थी। खराब प्रदर्शन के बाद हो रही आलोचना के बीच अरशद नदीम ने अपना नाम लॉजेन डायमंड लीग से वापस ले लिया है।

अरशद नदीम के लॉजेन डायमंड लीग नाम वापस लेने का मतलब यह है कि भारत-पाकिस्तान के दर्शकों को नीरज-चोपड़ा और नदीम की प्रतिस्पर्धा देखने को नहीं मिलेगी। यह प्रतियोगिता 21 अगस्त को होनी थी।

नदीम के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, वह फिलहाल लाहौर के पंजाब स्टेडियम में कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके बाद वह विदेश में ट्रेनिंग में लेंगे। जानकारी के मुताबिक, नदीम लॉजेन डायमंड लीग के बजाय एशियन गेम्स पर ध्यान देना चाहते हैं। इस आयोजन में बेहतर प्रदर्शन के उद्देश्य से कड़ी ट्रेनिंग के लिए दक्षिण अफ्रीका के पोटचेफस्ट्रूम जाने वाले हैं। पोटचेफस्ट्रूम में वह दो सप्ताह का कड़ा प्रशिक्षण लेंगे। यहां वह पहले दो बार ट्रेनिंग कर चुके हैं।

ट्रेनिंग कैप के बाद, नदीम के 6 से 14 सितंबर तक बुडापेस्ट में होने वाली वर्ल्ड



एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की उम्मीद है। इसके बाद वह एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगे।

अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक में 2024 में जैवलिन में स्वर्ण जीतकर पूरी दुनिया में नाम बनाया था, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उनके प्रदर्शन ने निराश किया है। हाल ही में खत्म हुए ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में, नदीम पुरुषों के जैवलिन

श्रो फाइनल में 77.41 मीटर के बेस्ट श्रो के साथ नौवें स्थान पर रहे। डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर कॉम्पिटिशन में शामिल होने के बाद, वह फाइनल के पहले तीन राउंड के बाद बाहर हो गए क्योंकि वह टॉप आठ में जगह बनाने में नाकाम रहे।

दक्षिण अफ्रीका में ट्रेनिंग के बाद अरशद नदीम की कोशिश एशियन गेम्स में दमदार वापसी पर है।

खुशी कपूर की पहचान का दुरुपयोग करने वालों पर सख्ती अश्लील कंटेंट और अनधिकृत बिक्री पर रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री खुशी कपूर की पहचान का कथित तौर पर दुरुपयोग करके बनाए गए अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट तथा उनकी अनुमति के बिना बेचे जा रहे सामान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने संबंधित पक्षों को ऐसे कंटेंट और उत्पादों को हटाने के निर्देश दिए हैं। पहचान के गलत इस्तेमाल पर कोर्ट सख्त मामले में अभिनेत्री की पहचान, नाम और छवि का कथित तौर पर बिना अनुमति इस्तेमाल किए जाने का मुद्दा उठाया गया था। कोर्ट के आदेश का उद्देश्य उनकी व्यक्तिगत पहचान और पब्लिसिटी राइट्स की रक्षा करना है।

अदालत ने कथित आपत्तिजनक सामग्री को ऑनलाइन उपलब्ध कराने और उनकी पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की दिशा में निर्देश जारी किए। अश्लील कंटेंट और अनधिकृत मर्चेंडाइज पर कार्रवाई मामले में ऐसे ऑनलाइन कंटेंट का भी मुद्दा सामने आया, जिसमें खुशी कपूर की पहचान का इस्तेमाल कथित रूप से अश्लील सामग्री तैयार करने के लिए किया गया था। इसके अलावा उनकी तस्वीरों या नाम का इस्तेमाल कर बिना अनुमति उत्पाद बेचने की शिकायत भी की गई थी। कोर्ट ने ऐसे कंटेंट और लिस्टिंग को हटाने के लिए संबंधित प्लेटफॉर्म और पक्षों को आवश्यक कदम उठाने को कहा। यह मामला ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल एडिटिंग टूल्स के जरिए किसी व्यक्ति की तस्वीर या पहचान का दुरुपयोग करके नकली कंटेंट तैयार करना आसान हो गया है। सेलिब्रिटीज के मामलों में ऐसे आदेश डिजिटल पहचान, प्राइवेसी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मिसाल बन सकते हैं।



मैं प्राकृतिक तरीके से मां बनने में विश्वास रखती हूँ: सुरभि चंदना

सेलिब्रिटीज के बीच एम्स फ्रीज करने के चलन को लेकर अभिनेत्री सुरभि चंदना ने अपनी एक अलग राय रखी है। एक्ट्रेस सुरभि ने स्पष्ट किया कि हालांकि वह उन सभी महिलाओं का पूरा समर्थन करती हैं जो अपने एम्स फ्रीज करने का निर्णय लेती हैं, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। उनका मानना है कि वह चीजों को उनके प्राकृतिक तरीके से ही होने देने में विश्वास रखती हैं, खासकर मातृत्व के संबंध में। नागिन फेम एक्ट्रेस सुरभि से जब इस बढ़ते ट्रेंड के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपनी बड़ी बहन का एक उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि उनकी बहन ने 39 साल की उम्र में बिना किसी मेडिकल मदद के स्वाभाविक रूप से एक बेटे को जन्म दिया था। वह बच्चा अब दो साल का है, और डिलीवरी भी सामान्य थी। यह अनुभव सुरभि के लिए एक प्रेरणा है और उनके प्राकृतिक दृष्टिकोण का आधार है। उन्होंने बताया, मैं इसमें विश्वास रखती हूँ, और जो लोग एम्स फ्रीज करना जरूरी समझते हैं, वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया था, अगर आप ऐसा करती हैं तो बहुत ज्यादा हार्मोनल असंतुलन हो सकता है।

सुरभि ने आगे कहा कि उनका मानना है कि हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर इस दुनिया में आता है। भविष्य के बारे में अनिश्चितता जताते हुए उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बहन, जिसकी नौकरी में बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है और जिसका शरीर बहुत ज्यादा तनाव से गुजरता है, अगर वह नैचुरली बच्चे को जन्म दे सकती है, तो मैं भी नैचुरल तरीका ही अपनाना चाहती हूँ। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें अभी भी एम्स फ्रीज करने की प्रक्रिया से जुड़े हार्मोनल असंतुलन के संभावित खतरों से थोड़ा डर लगता है। यह डर उनकी प्राकृतिक प्रक्रिया पर भरोसा करने के पीछे एक मुख्य कारण है। अपने भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि हम कब प्लान करेंगे, लेकिन यह सही समय आने पर ही होगा। जब भी ऐसा होगा, यह भगवान का तोहफा होगा।

अमेरिका में 'बर्थ टूरिज्म' के खिलाफ अभियान तेज, 600 से ज्यादा विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द

» वॉशिंगटन, यूटर्न/ 13 अगस्त

अमेरिका ने 'बर्थ टूरिज्म' के खिलाफ एक नए अभियान के तहत 600 से ज्यादा विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी।

विदेश विभाग ने बताया कि उसने 'बर्थ टूरिज्म प्रिवेंशन टास्क फोर्स' नाम की एक विशेष टीम बनाई है। इसका काम उन वीजा धारकों की पहचान करना है जो अमेरिका में बच्चे को जन्म देने के लिए वहां गए थे। साथ ही, उन लोगों और नेटवर्क का पता लगाना भी है जो ऐसी यात्राओं की व्यवस्था करते हैं।

यह टास्क फोर्स दुनिया भर के वीजा धारकों की गतिविधियों और यात्रा इतिहास की समीक्षा करती है। इसके अलावा यह विदेश विभाग, होमलैंड सिक्वोरिटी विभाग और अन्य संघीय एजेंसियों के पास मौजूद जानकारी का भी विश्लेषण करती है।

इसका उद्देश्य 'बर्थ टूरिज्म' से



जुड़े मामलों की पहचान करना, वीजा रद्द करना और इस गतिविधि से कमाई करने वाले नेटवर्क को खत्म करना है। विदेश विभाग ने एक फैक्ट शीट में कहा, 'बर्थ टूरिज्म टास्क फोर्स ने इस दुरुपयोग से देश की सुरक्षा के लिए दुनिया भर के विदेशी नागरिकों के 600 से अधिक वीजा रद्द किए हैं।'

विभाग ने कहा कि आम तौर पर वीजा तब रद्द किए जाते हैं जब किसी व्यक्ति के वीजा के लिए अयोग्य होने के संकेत मिलते हैं। विदेश मंत्री मार्को रुबियो के पास वीजा रद्द करने का व्यापक अधिकार है।

पीओके में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ बेलजियम में कश्मीरी समुदाय ने निकाला मार्च

» ब्रसेल्स, यूटर्न/ 13 अगस्त ।

बेलजियम में रहने वाले कश्मीरी समुदाय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों की निंदा की गई। कश्मीरी समुदाय ने राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट से यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस तक एक विरोध मार्च निकाला।

प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए गए और पीओके में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने की मांग की। इन उल्लंघनों में जरूरी सेवाओं पर रोक और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का क्रूर इस्तेमाल शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने पीओके में पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से की गई क्रूर कार्रवाई के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की। इस हफ्ते की शुरुआत में पीओके स्थित मानवाधिकार दस्तावेजीकरण और निगरानी संस्था जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार वेधशाला (जेकेएचआरओ) ने 5 जून से 5 अगस्त के बीच कब्जे वाले इलाके में बढ़ती अशांति के दौरान 93 नागरिकों की मौत दर्ज की। पिछले हफ्ते हजारों कश्मीरी प्रवासियों ने इटली के बोलोग्ना शहर में विरोध मार्च निकाला और पीओके में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के

खिलाफ पाकिस्तानी सेना की क्रूरता की निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने नागरिक



समाज समूह 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (जेएएस) के साथ एकजुटता व्यक्त की और क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के अभियानों को समाप्त करने की मांग की। जेएएस ने सोशल मीडिया पर कहा कि इटली में कश्मीरियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे पाकिस्तानी सेना द्वारा निहत्थे नागरिकों के 'नरसंहार' के खिलाफ आवाज उठाएं। उन्होंने कहा, 'शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी केवल अपने बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे हैं।' हाल ही में, कई ब्रिटिश सांसदों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पीओके में नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की क्रूरता पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। ब्रिटिश लेबर पार्टी के सांसद लियाम बायरन ने कहा था कि पीओके में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोलीबारी की खबरें बेहद चिंताजनक हैं।

बांग्लादेश भागने की फिराक में था पाकिस्तानी जासूस वहाब आलम, पूछताछ में बड़े खुलासे

» कोलकाता, यूटर्न/ 13 अगस्त ।

पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले में स्थित हाबरा से गिरफ्तार पाकिस्तानी नागरिक वहाब आलम कुछ समय के लिए बांग्लादेश भागने की फिराक में था। वह बांग्लादेश में कुछ समय बिताकर नई पहचान और नए काम के साथ वापस पश्चिम बंगाल लौटना चाहता था। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की



पूछताछ में वहाब आलम ने कई अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के अनुसार उसे पाकिस्तान की

खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भेजा था। उसका काम देश के पूर्वी हिस्से में भारतीय सेना, नौसेना और रेलवे की जानकारी जुटाना था। पूछताछ में वहाब आलम ने बताया कि पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं ने उसे सलाह दी थी कि वह कुछ समय के लिए बांग्लादेश चला जाए। एसटीएफ ने आलम के नेटवर्क की जांच के दौरान बांग्लादेश में मौजूद एक आईएसआई एजेंट पवेल की जानकारी भी

हासिल की है। वहाब आलम को बांग्लादेश भागने के बाद इसी पवेल से मिलना था।

सूत्रों ने बताया कि पवेल अभी बांग्लादेश के जेसोर में सक्रिय है। उसे वहाब आलम आलम के लिए बांग्लादेश में कुछ समय के लिए सुरक्षित ठिकाना तय करना था। इसके बाद उसे पश्चिम बंगाल में मिलने वाले नए काम की जानकारी देनी थी और फिर कुछ समय बाद उसे वापस राज्य में भेजना था।

बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान और सिंध में मौजूद पाकिस्तानी सेना के अहम ठिकानों पर किया हमला



इस्तेमाल कर हमला किया। हमले में चार सैन्य कर्मी मारे गए, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

मजार बलूच के मुताबिक, यूबीए लड़ाके दर्ज बीट और पंजरा ब्रिज चेकपोस्ट के बीच सेना की गतिविधि पर करीब से नजर रख रहे

थे, और इलाके में काफिलों और जवानों के आने जाने की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। वहीं, द बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (बीआरजी) प्रवक्ता दोस्तैन बलूच ने कहा कि उनके लड़ाकों ने मंगलवार रात बलूचिस्तान के

नसीराबाद जिले में चत्तर के पास दो 220केवी के बिजली टावरों पर धमाका किया था। टावरों पर विस्फोटक लगाए गए थे, जिससे दोनों को बहुत नुकसान हुआ।

बीआरजी ने 9 अगस्त को भी इसी तरह का हमला करने का दावा किया। बयान में कहा गया कि उनके लड़ाकों ने बलूचिस्तान के कच्छी जिले स्थित धादर इलाके में एक कृषि कार्यालय को विस्फोटक लगा उड़ा दिया, जिसमें इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। ग्रुप का आरोप है कि यहां से 'कब्जे वाले पाकिस्तानी देश' बलूचिस्तान में कृषि क्षेत्र को खत्म करने की साजिश रची जाती थी। इसी हफ्ते की शुरुआत में, बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर किए गए 38 हमलों की जिम्मेदारी ली थी। उनका कहना था कि इस अभियान में 32 सैन्य कर्मी और उनके मददगार मारे गए थे, जबकि कई घायल हो गए थे।

मध्यावधि चुनाव से पहले ट्रंप का बड़ा संकेत, मतदाता पहचान के लिए लगा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल

» वॉशिंगटन, यूटर्न/ 13 अगस्त ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दिया है कि वह अमेरिका के मध्यावधि चुनावों से पहले मतदाता पहचान और नागरिकता सत्यापन को अनिवार्य बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल घोषित करने की संभावना पर विचार कर सकते हैं।

ट्रंप ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उनके इस बयान ने चुनावी नियमों, मतदाता अधिकारों और संघीय सरकार की शक्तियों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

ट्रंप ने 'रियल अमेरिकान वायस' पर वेन एलिन रूट को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'इससे भी ज्यादा असामान्य चीजें पहले हो चुकी हैं। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा।'

रूट ने ट्रंप से कहा कि अगर सीनेट 'सेव अमेरिका एक्ट' को मंजूरी नहीं देती, तो उन्हें आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। रूट ने सुझाव दिया कि ऐसी शक्तियों के जरिए फोटो पहचान पत्र, नागरिकता का प्रमाण अनिवार्य किया जा सकता है और डाक के जरिए भेजे जाने वाले मेल-इन बैलेट पर भी सीमाएं लगाई जा सकती हैं।

ट्रंप ने इस प्रस्ताव का साफ तौर पर समर्थन नहीं किया, लेकिन उन्होंने बार-बार कहा कि मध्यावधि चुनावों से पहले चुनावी नियमों पर सीनेट को कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रंप ने कहा, 'सीनेट को 'सेव अमेरिका एक्ट' पर आगे बढ़ना होगा। मुझे सच में लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि लोग इसकी उम्मीद कर रहे हैं और यह जरूरी भी है।' उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि नागरिकता का प्रमाण हो। और मतदाता पहचान पत्र भी होना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि कुछ रिपब्लिकन सीनेटर इन उपायों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने हाउस स्पीकर माइक जॉनसन की तारीफ की



और कहा कि प्रतिनिधि सभा इस कानून को पांच बार मंजूर कर चुकी है, लेकिन यह हर बार सीनेट में जाकर अटक जाता है।

राष्ट्रपति ने डाक से मतदान की व्यवस्था की भी फिर से आलोचना की। उन्होंने बिना कोई सबूत दिए दावा किया कि यह प्रणाली धोखाधड़ी के लिए संवेदनशील है और खास तौर पर कैलिफोर्निया की चुनावी व्यवस्था पर निशाना साधा। ट्रंप ने कहा कि मेल-इन बैलेट्स बहुत भ्रष्ट हैं।

उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया चुनावों के मामले में सबसे भ्रष्ट जगहों में से एक है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कुछ क्षेत्रों में रिपब्लिकन मतदाताओं को मतपत्र प्राप्त करने में कठिनाई होती है। रूट ने ट्रंप से कहा कि चुनाव संबंधी यह कानून शायद सीनेट से मंजूरी न पा सके। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इसे पारित कर भी दे, तब भी इसे तुरंत कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद रूट ने ट्रंप से आग्रह किया कि वे अगले एक महीने के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल घोषित करें। रूट का दावा था कि इससे प्रशासन सीनेट की मंजूरी का इंतजार किए बिना फोटो पहचान पत्र, नागरिकता प्रमाण की अनिवार्यता और मेल-इन वोटिंग पर सीमाएं लागू कर सकेगा।

संक्षिप्त खबरें

कोलंबिया के राष्ट्रपति ने भूकंप के बाद आर्थिक आपातकाल घोषित किया

मेक्सिको सिटी, यूटर्न/ 13 अगस्त । कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलार्दो दे ला एस्पिरला ने 10 अगस्त को आये शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए संवैधानिक आर्थिक आपातकाल घोषित किया है तथा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष कोष बनाने की घोषणा की है। श्री एस्पिरला ने कैराकोल टेलीविजन चैनल पर प्रसारित बयान में कहा, 'मैंने इस संकट से उचित तरीके से निपटने के लिए संविधान में निर्धारित आर्थिक आपातकाल लागू करने का निर्णय लिया है।' नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भूकंप से 53,526 मकानों को नुकसान पहुंचा है और 140 इमारतें पूरी तरह ढह गयी हैं। इसके अलावा 1,819 शैक्षणिक संस्थानों, 631 सामुदायिक केंद्रों और 179 स्वास्थ्य सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है।

कुवैत ने आईएसआईएस के हमले की साजिश को नाकाम किया

कुवैत सिटी, यूटर्न/ 13 अगस्त । कुवैत की राज्य सुरक्षा सेवा ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) से जुड़े एक कुवैती नागरिक को गिरफ्तार करके एक अहम बुनियादी ढांचे पर हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। कुवैत के गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा, 'सुरक्षा बलों ने देश के एक अहम ठिकाने को निशाना बनाने की आतंकवादी साजिश को नाकाम करते हुए आईएसआईएस के एक आतंकवादी को उसकी योजना को अंजाम देने से पहले ही हिरासत में ले लिया।' बयान के मुताबिक हिरासत में लिये गये व्यक्ति ने विस्फोटक और बिना पायलट वाले हवाई वाहनों (यूएवी) को बनाने का प्रशिक्षण लिया था। उसने एक ड्रोन भी बनाया था, जिसका इस्तेमाल वह हमले में करने वाला था। बयान में कहा गया है कि संदिग्ध के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की गयी है और उसे जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है।